# मेन्स मास्टर

## Drug war

### संदर्भ

यह लेख भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर), सर्वेक्षण खुलासे (टीएचएस में शामिल), एंटीबायोटिक दुरुपयोग के चालकों, स्वास्थ्य देखभाल से परे व्यापक प्रासंगिक कारकों, प्रस्तावित समाधानों और सामूहिक कार्रवाई के आह्वान पर प्रकाश डालता है। यह व्यापक-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं की व्यापकता, क्षेत्रीय विविधताओं और रोगी दबाव और आर्थिक प्रोत्साहन जैसे दुरुपयोग चालकों पर जोर देता है। यह एएमआर से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा, सख्त नियमों, वैकल्पिक उपचारों और सामुदायिक भागीदारी में हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। लक्ष्य इस वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के लिए एक ठोस प्रयास के लिए कई हितधारकों को शामिल करते हुए जिम्मेदार प्रथाओं और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

**भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर गहराई से विचार:**

1. **सर्वेक्षण के खुलासों पर विस्तार:**

• **एंटीबायोटिक दवाओं के प्रकार:** सर्वेक्षण में न केवल उच्च समग्र एंटीबायोटिक उपयोग का पता चला, बल्कि उच्च एएमआर क्षमता वाले व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं के प्रसार पर भी प्रकाश डाला गया। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह प्रतिरोधी बैक्टीरिया के चयन के दबाव को बढ़ाता है।

• **क्षेत्रीय विविधताएं:** सर्वेक्षण में 15 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया, लेकिन डेटा एंटीबायोटिक उपयोग पैटर्न में क्षेत्रीय विविधताओं का सुझाव देता है। इन विविधताओं को समझने से विशिष्ट क्षेत्रों में हस्तक्षेप तैयार करने में मदद मिल सकती है।

• **अस्पताल के प्रकार:** सर्वेक्षण तृतीयक देखभाल अस्पतालों पर केंद्रित है, लेकिन प्राथमिक देखभाल और सामुदायिक सेटिंग्स में एएमआर भी एक चिंता का विषय है। विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल स्तरों पर एंटीबायोटिक के उपयोग की जांच करना महत्वपूर्ण है।

2. **दुरुपयोग करने वाले चालकों को खोलना:**

• **ज्ञान में कमी:** कई स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, विशेष रूप से निजी सेटिंग्स में, उचित एंटीबायोटिक उपयोग और एएमआर जोखिमों पर पर्याप्त ज्ञान या प्रशिक्षण की कमी हो सकती है।

• **रोगी का दबाव:** मरीज अक्सर एंटीबायोटिक दवाओं की मांग करते हैं, यहां तक कि स्व-निदान स्थितियों या वायरल संक्रमण के लिए भी। यह दबाव डॉक्टरों के निर्धारित निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

• **आर्थिक प्रोत्साहन:** निजी स्वास्थ्य देखभाल में, वित्तीय प्रोत्साहन अनावश्यक एंटीबायोटिक्स या व्यापक-स्पेक्ट्रम दवाओं को निर्धारित करने को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

• **उपलब्धता और सामर्थ्य:** बिना नुस्खे के भी एंटीबायोटिक दवाओं की आसान पहुंच और सामर्थ्य, समुदायों में दुरुपयोग में योगदान करती है।

3. **स्वास्थ्य सेवा से परे:** व्यापक संदर्भ को संबोधित करना:

• कृषि और पशुपालन में एंटीबायोटिक का उपयोग: पशुधन में विकास प्रवर्तकों के रूप में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग एएमआर विकास और भोजन और पर्यावरण के माध्यम से मनुष्यों में स्थानांतरण में योगदान देता है।

• **पर्यावरण प्रदूषण:** स्वास्थ्य देखभाल और पशु फार्मों से फार्मास्युटिकल कचरे का अनुचित निपटान पानी और मिट्टी को प्रदूषित करता है, जिससे प्रतिरोधी बैक्टीरिया के प्रसार को बढ़ावा मिलता है।

• **जन जागरूकता की कमी:** बहुत से लोग अभी भी एएमआर के खतरे को नहीं समझते हैं और एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग करना जारी रखते हैं। व्यवहार परिवर्तन के लिए सार्वजनिक शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण हैं।

4. **एएमआर से निपटना: एक बहुआयामी दृष्टिकोण:**

• नियमों को मजबूत करना: सरकारों को एंटीबायोटिक की बिक्री, वितरण और निर्धारित प्रथाओं पर सख्त नियमों को लागू करने की आवश्यकता है।

• **स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा में सुधार:** एएमआर और तर्कसंगत एंटीबायोटिक उपयोग पर स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा में निवेश करना आवश्यक है।

• **वैकल्पिक उपचारों को बढ़ावा देना:** सामान्य संक्रमणों के लिए गैर-एंटीबायोटिक उपचारों के अनुसंधान और विकास का समर्थन करने से एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भरता कम हो सकती है।

• **निगरानी और अनुसंधान को मजबूत करना:** एएमआर रुझानों की लगातार निगरानी करना और नए एंटीबायोटिक्स और नैदानिक उपकरणों पर अनुसंधान में निवेश करना महत्वपूर्ण है।

• **सामुदायिक भागीदारी:** उचित एंटीबायोटिक उपयोग और जिम्मेदार स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान और शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

## भारत की राजनीति में विश्वास वापस लाना

यह लेख भारत के लोकतंत्र संकट को उजागर करता है, अंध-वफादारी पर मुद्दा-केंद्रित राजनीति की वकालत करता है, दल-बदल विरोधी कानूनों को खत्म करने का प्रस्ताव करता है, जिम्मेदार पत्रकारिता पर जोर देता है, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच एकता का आह्वान करता है, ताकि भारत को वैश्विक स्तर पर न्यायपूर्ण समाज के लिए विविधता में एकता का मॉडलरूप स्थापित किया जा सके।

**टूटता भरोसा: चौराहे पर एक संकट**

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। जबकि इसके आकार और प्रभाव को वैश्विक मंच पर सम्मान मिलता है, इसका घरेलू राजनीतिक परिदृश्य विश्वास के संकट से घिरा हुआ है। रचनात्मक संवाद की जगह पक्षपातपूर्ण रणनीति ने ले ली है और अविश्वास के बोझ से लोकतंत्र की नींव कांपने लगी है।

विश्वास का यह ह्रास कई तरीकों से प्रकट होता है। सत्तारूढ़ सरकार लोकतांत्रिक बारीकियों के प्रति अधीरता प्रदर्शित करती है, असहमति को दबाने के लिए राज्य की शक्ति का इस्तेमाल करती है और स्थापित मानदंडों की अवहेलना करती है। दूसरी ओर, विपक्ष का एक वर्ग सार्थक बातचीत के बजाय सरकार को शर्मिंदा करने को प्राथमिकता देता है। यह निरंतर नकारात्मकता संशय को बढ़ावा देती है और भारतीय लोकतंत्र की पोल खुलने का खतरा पैदा करती है।

**विश्वास बहाल करना: एक बहुआयामी दृष्टिकोण**
हालाँकि, इस निराशाजनक परिदृश्य के बीच, आशा बनी हुई है। लेख इस संकट से निपटने और भारतीय लोकतंत्र में विश्वास को फिर से जगाने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है।
**परिवर्तन के एजेंट के रूप में पार्टी सदस्य:**
सबसे पहले जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों की है। उन्हें उस अंध आदिवासीवाद को अस्वीकार करना चाहिए जो निर्विवाद निष्ठा की मांग करता है और इसके बजाय अपनी पार्टियों को ठोस मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए अपरिहार्य और प्राथमिकता वाली बातचीत का बचाव करने और जनता की भलाई के लिए सामान्य आधार खोजने के दबाव का विरोध करने की आवश्यकता है।
**व्यवस्था में सुधार: दल-बदल विरोधी कानून को समाप्त करना**
लोकतंत्र के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित व्यक्ति, अपने राजनीतिक झुकाव की परवाह किए बिना, विवादास्पद दल-बदल विरोधी कानून को हटाने की वकालत कर सकते हैं। यह कानून, दल-बदल को रोकने के उद्देश्य से, विडंबनापूर्ण है कि आंतरिक पार्टी लोकतंत्र में बाधा डालता है और पार्टी लाइनों के पार मुद्दा-आधारित सहयोग को हतोत्साहित करता है। इसका उन्मूलन एक अधिक तरल राजनीतिक परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त करेगा जहां समझौता और सहयोग पनप सकता है।
**अच्छाई के लिए एक शक्ति के रूप में मीडिया**: जिम्मेदार पत्रकारिता के माध्यम से विश्वास का पुनर्निर्माण
**अंत में,** मीडिया को विश्वास के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की जिम्मेदार रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो सनसनीखेज पर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देती है। केवल नैतिक पत्रकारिता के प्रति सचेत बदलाव के माध्यम से ही मीडिया स्वस्थ लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका फिर से हासिल कर सकता है।
ड्राइंग प्रेरणा: इज़राइल से सबक
यह लेख इज़राइल में हाल की घटनाओं से प्रेरणा लेता है, जहां विभिन्न हितधारक सरकारी अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में एकजुट हुए थे। यह भारत के लिए आशा की एक किरण प्रदान करता है, यह सुझाव देता है कि सभी विचारधाराओं के चिंतित नागरिक अपने नाजुक लोकतंत्र को संरक्षित करने के लिए एक साथ आ सकते हैं।
**कार्रवाई का आह्वान: लोकतंत्र की सामूहिक पुनः प्राप्ति के लिए**
**संदेश स्पष्ट है**: वैश्विक लोकतंत्र के लिए आशा की किरण के रूप में भारत का भविष्य सामूहिक प्रयास पर निर्भर है। पार्टी के सदस्यों को अंध-वफादारी से मुक्त होना चाहिए, अधिवक्ताओं को हानिकारक कानूनों को चुनौती देनी चाहिए और मीडिया को अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। केवल ऐसी ठोस कार्रवाई के माध्यम से ही भारत अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को पुनः प्राप्त कर सकता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
**चुनौती बहुत बड़ी है,** लेकिन संभावित पुरस्कार भी उतने ही विशाल हैं। यदि भारत इस संकट से निपट सकता है और एक जीवंत और भरोसेमंद लोकतंत्र के रूप में उभर सकता है, तो यह न केवल अपने नागरिकों की सेवा करेगा, बल्कि दुनिया के सामने एक शक्तिशाली उदाहरण भी पेश करेगा कि कैसे विविध लोग एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं।

• समर्पित वन कर्मचारी बाघों और दुष्ट हाथियों का पीछा करने जैसे खतरों का सामना करते हुए, रिजर्व की रक्षा और प्रबंधन करते हैं।
• **बेहतर कार्यप्रणाली:** कर्मचारियों के लिए समय पर वेतन, राशन, हथियार, चिकित्सा सहायता; अनुभव साझा करने और नीति निर्धारण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जुड़ाव।
• **वन और वन्यजीव प्रबंधन के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण:**
  ◦ चीतल और सांभर जैसे शिकारी जानवरों के लिए घास के मैदान का प्रबंधन।
  ◦ वन्यजीवों की जरूरतों के लिए सौर-पंप से पोषित जल छिद्रों की रणनीतिक नियुक्ति।
  ◦ जीन पूल विनिमय और टिकाऊ प्रबंधन के लिए वन्यजीव गलियारों का विकास।
  ◦ गहन गश्त और डिजिटल निगरानी के माध्यम से अवैध शिकार पर मजबूत नियंत्रण।
**चुनौतियाँ:**
• **मानव-वन्यजीव संघर्ष:**
  ◦ बाघों की आबादी बढ़ने से पशुधन और बफर जोन में जाने वाले ग्रामीणों पर हमले हो रहे हैं।
  ◦ निजी स्वामित्व वाली भूमि और निर्माण गतिविधियाँ जानवरों की आवाजाही को सीमित करती हैं।
• सामुदायिक लाभ की आवश्यकता:
  ◦ रिजर्व के आसपास के ग्रामीणों को जोखिम और फसल छापे का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे रोजगार के लिए इकोटूरिज्म पर भी निर्भर रहते हैं।
  ◦ वन विभाग को ग्रामीणों से "इच्छुक सहयोग" प्राप्त करने के लिए सहयोगी और सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होने की आवश्यकता है।
**पहल:**
• **मधुमक्खी के छत्ते की बाड़ लगाने की परियोजना:** रणनीतिक रूप से लगाए गए मधुमक्खी के छत्ते हाथियों को फसलों पर हमला करने से रोकते हैं।
• **"लिविंग विद टाइगर्स" पहल:** ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को मानव-वन्यजीव संघर्ष और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करती है।
कुल मिलाकर:
• कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वन्यजीव संरक्षण में एक सफलता की कहानी है, लेकिन मानव-वन्यजीव संघर्ष और सामुदायिक लाभ की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का सामना करता है।
• सहयोगात्मक प्रयास और सार्वजनिक पहल रिजर्व, इसके वन्य जीवन और इसके लोगों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

## प्रीलिम्स बूस्टर

**बाघ का पुनरुद्धार, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व: संरक्षण की सफलता और चुनौतियों की एक कहानी**

सदर्भ
यह लेख जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या में वृद्धि, वन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका, वन्यजीवों और आवासों के लिए प्रबंधन रणनीतियों और संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने वाली पहलों पर केंद्रित है। संरक्षण प्रयास की सफलता को निबंध और जीएस उत्तरों में उद्धृत किया जा सकता है।

**संरक्षण की सफलता:**
• **बाघों की आबादी बढ़ी:** 2018 में 231 से 2022 में 260, दुनिया में सबसे अधिक घनत्व।
• समृद्ध वन और जैव विविधतापूर्ण परिदृश्य शोधकर्ताओं, पर्यटकों और संरक्षणवादियों को आकर्षित करता है।

**कैबिनेट ने पृथ्वी अवलोकन के लिए 'पृथ्वी' कार्यक्रम को मंजूरी दी**

🔍 पहल का नाम: पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी)
💰 कुल आवंटित धनराशि: पांच वर्षों में 4,797 करोड़ रुपये
🎯 उद्देश्य: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के तहत पृथ्वी विज्ञान से संबंधित विभिन्न उप-योजनाओं में अनुसंधान प्रयासों को एकीकृत करना
🌐 कवर की गई उप-योजनाएँ:
- वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएँ
- महासागर सेवाएँ, मॉडलिंग अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी

- ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान
- भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान
- अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच

🌟 मुख्य विशेषताएं:
- समग्र दृष्टिकोण: एक एकीकृत इकाई के रूप में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है
- अंतर-विषयक परियोजनाएं: संयुक्त अनुसंधान प्रयासों को सक्षम बनाती हैं
- अनुसंधान की सुविधा: इसका उद्देश्य अनुसंधान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाना है

🎯 उद्देश्य:
- पृथ्वी प्रणाली और परिवर्तनों के महत्वपूर्ण संकेतों का दीर्घकालिक अवलोकन और रिकॉर्डिंग
- मौसम, महासागर और जलवायु खतरे की भविष्यवाणी के लिए मॉडलिंग सिस्टम का विकास
- नई घटनाओं और संसाधनों के लिए ध्रुवीय और उच्च समुद्री क्षेत्रों की खोज
- समुद्री संसाधनों के सतत दोहन के लिए प्रौद्योगिकी विकास

🚀 कार्यान्वयन:
- इसमें MoES के तहत 10 अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग शामिल है
- आवश्यक अनुसंधान सहायता के लिए समुद्र विज्ञान और तटीय अनुसंधान जहाजों का उपयोग

## एनएसओ का कहना है कि भारत की जीडीपी 7.3% बढ़ने का अनुमान है

📈 जीडीपी वृद्धि अनुमान: 2023-24 के लिए 7.3% अनुमानित, आरबीआई के 7% के अनुमान से थोड़ा अधिक

🪫 चिंताएँ: 4.4% पर कमजोर उपभोग वृद्धि, संभावित राजकोषीय घाटा

🌾 क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि: कृषि और कुछ सेवा क्षेत्रों में मंदी दिख रही है, जबकि विनिर्माण और निर्माण में मजबूत वृद्धि बनी हुई है।

💬 विशेषज्ञ राय: अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि कुछ अनुमान अत्यधिक आशावादी हो सकते हैं, खासकर कृषि उत्पादन और उपभोग व्यय के संबंध में

🔍 एनएसओ की सावधानी: अनुमान प्रारंभिक हैं और बेहतर डेटा कवरेज और बाद के आर्थिक संकेतकों के आधार पर संशोधन के अधीन हैं

📅 स्थापना: सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद 15.10.1999 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का गठन हुआ।

🏛️ संरचना: दो विंग - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन

📊 सांख्यिकी विंग: इसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) शामिल है जिसमें केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) शामिल हैं।

📋 कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग: इसमें बीस सूत्रीय कार्यक्रम, बुनियादी ढांचे की निगरानी और परियोजना निगरानी, और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रभाग शामिल हैं

## जुआरी फार्महब ने नैनो उर्वरक लॉन्च किया

नैनोउर्वरक नैनोमटेरियल्स के भीतर संपुटित या लोपित विशेष पोषक तत्व हैं, जो मिट्टी में पोषक तत्वों के नियंत्रित रिलीज और धीमी गति से प्रसार की अनुमति देते हैं।

🌱 नियंत्रित विमोचन: नैनोउर्वरक धीरे-धीरे पोषक तत्वों को छोड़ते हैं, जिससे लीचिंग, क्षरण और अपवाह द्वारा पोषक तत्वों की हानि कम हो जाती है।

🚀 बढ़ी हुई दक्षता: उच्च सतह क्षेत्र से आयतन अनुपात पौधों को पोषक तत्वों की कुशल डिलीवरी की अनुमति देता है।

🌍 पर्यावरणीय लाभ: लीचिंग और अपवाह को कम करके पर्यावरणीय खतरों को कम करें।

🌾 कृषि संबंधी लाभ: पौधों की वृद्धि प्रक्रियाओं और तनाव सहनशीलता को प्रोत्साहित करना, संभावित रूप से फसल की उपज और गुणवत्ता में वृद्धि करना।

## भारत संयुक्त अरब अमीरात में 'विशिष्ट व्यापार क्षेत्र' स्थापित करेगा

🌐 उद्देश्य: संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क वैश्विक दर्शकों के लिए भारत में बनी वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहीत करने के लिए भारत-विशिष्ट व्यापार क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।

🎯 उद्देश्य: संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षित भुगतान के साथ भारतीय वस्तुओं की वैश्विक बिक्री की सुविधा प्रदान करना।

🛡️ गुणवत्ता आश्वासन पहल:
- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस): पूरे भारत में 21 परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिए ₹40 करोड़ का आवंटन।
- गुणवत्ता पर जोर: निर्यातित वस्तुओं के लिए उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करना।

🧪 कपड़ा उद्योग फोकस:
- मानव निर्मित फाइबर कपड़ा: कपास की आपूर्ति में सीमाओं के कारण सिंथेटिक और रेयान कपड़ा उद्योग की क्षमता पर प्रकाश डालना।
- निर्यात संबंधी चिंताएँ: मानव निर्मित फाइबर कपड़ा निर्यात में 9% की गिरावट दर्ज की गई है लेकिन तकनीकी कपड़ा निर्यात में मामूली सुधार हुआ है।
- आशावादी दृष्टिकोण: इस वित्तीय वर्ष में कपड़ा निर्यात में $6 बिलियन और तकनीकी कपड़ा शिपमेंट में $3 बिलियन को पार करने का लक्ष्य है।

🤝 व्यापार समझौते और भविष्य के लक्ष्य:
- उपयोग को प्रोत्साहित करना: उद्योग से जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने का आग्रह करना।
- निर्यात लक्ष्य: 2030 तक मानव निर्मित फाइबर में 11 बिलियन डॉलर और तकनीकी कपड़ा निर्यात में 10 बिलियन डॉलर के सरकारी लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य।

## कॉर्बेट नेशनल पार्क

🌳 स्थापना: 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया, जिसका नाम संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम मैल्कम हैली के नाम पर रखा गया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान

🏞️ नामकरण: 1956 में, भारत को आजादी मिलने के बाद, प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के सम्मान में इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जिन्होंने पार्क की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

🐅 प्रोजेक्ट टाइगर: बाघों और उनके आवासों के संरक्षण पर जोर देते हुए प्रोजेक्ट टाइगर पहल में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान।